



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

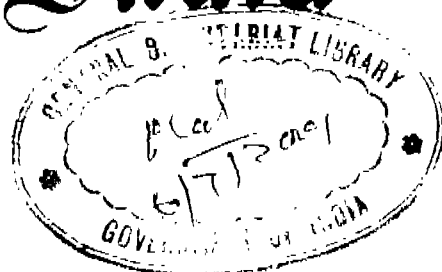
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 34 ]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 18, 2001/पौष 28, 1922

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2001/PAUSA 28, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001

**का.आ. 52(अ).—**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 1 और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अधिसूचना, जिसके द्वारा, महाबलेश्वर पंचगणी को पारिस्थितिक संवेदनशील प्रदेश के रूप में अधिसूचित करने वाली और उस प्रदेश में ऐसे उद्योगों, संक्रियाओं, प्रसंस्करणों और अन्य विकासशील क्रियाकलापों पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाली जिनका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, अधिसूचना के विरुद्ध आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे, का.आ. सं.693(अ), तारीख 25 जुलाई, 2000 में प्रकाशित की गई थी।

और प्राप्त सभी आक्षेपों या/और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाबलेश्वर पंचगणी प्रदेश को (जैसा कि महाराष्ट्र सरकार की तारीख 29 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में परिभाषित किया गया है), (जिसकी प्रति उपाबंधों के रूप में संलग्न है) पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में अधिसूचित करती है। इस प्रदेश में महाबलेश्वर तहसील की सीमाओं और महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले की जावली तहसील के बोंडारवाडी भूतेगढ़ दानवाली, तलोसी और उबरी गांवों की सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित होगा।

1. वनों में सभी क्रियाकलाप (नगर पालिका क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में सभी क्रियाकलाप वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

2. पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में विनियमित किए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों की प्रतिस्थापना की जाती है।

**(क) आंचलिक मास्टर प्लान :-**

- (i) सम्पूर्ण अंचल के लिए एक मास्टर प्लान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी। मास्टर प्लान को प्रकाशित करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966 के अधीन विहित है। मास्टर प्लान उन परिसीमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से उपदर्शित कर सकेगी जहां उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
- (ii) उक्त मास्टर प्लान सभी विद्यमान वनों, हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, जैसे स्ट्राबेरी फार्मों, रसभरी फार्मों, फलोद्यानों, जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पर्यावरणिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करेगी। हरित उपयोगों जैसे उद्यान, कृषि क्षेत्रों, कृषि उद्यानों और अन्य ऐसे ही स्थानों से भूमि के उपयोग का कोई परिवर्तन मास्टर प्लान में गैर-हरित उपयोगों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मास्टर प्लान में यातायात को, विशेषकर पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में होकर जानेवाले यातायात को विनियमित करने के लिए उपाय इंगित किए जाएंगे और अनुबंध अधिकथित किए जाएंगे।
- (iii) महाबलेश्वर और पंचगणी नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर और बाहर क्षेत्रों में उप आंचलिक मास्टर प्लान होंगे जो आंचलिक मास्टर प्लान के घटक के रूप में राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा सकेंगी और उस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी।

इस उप आंचलिक मास्टर प्लान में गोशान क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण विनियमों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

- (iv) ऊपर निर्दिष्ट आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन तक अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात, अनुज्ञेय ऊंचाई मंजिलों की अनुज्ञेय अधिकतम संख्या और अनुज्ञेय भू सीमा क्षेत्र के विद्यमान प्राचलों में कोई वृद्धि नहीं होगी और वन अंचल/हरित अंचल/कृषि अंचल में भी कोई कमी नहीं होगी। भवनों की आंत्यतिक ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होगी और मंजिलों की संख्या भूतल धन एक से अधिक नहीं होगी।

**(ख) औद्योगिक इकाईयां :-**

- (i) उद्योगों की स्थिति केवल अभिहित औद्योगिक क्षेत्रों या संपदाओं में होगी और वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय किए गए मार्गदर्शनों और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार होगी। तथापि, यह ऐसी उन सभी इकाईयों को लागू नहीं होंगे जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को या उससे पूर्व उन्हें स्थापित करने की सम्मति और अन्य सभी कानूनी अनुज्ञाएं अभिप्राप्त कर ली हैं तथा स्थल पर सन्निर्माण प्रारंभ कर दिया है।
- (ii) भविष्य में केवल अप्रदूषित, अपरिसंकटमय सेवा वाले ऐसे उद्योगों, एककों को, जो प्रसंस्कृत और तैयार चमड़े से जूते बनाते हो, तथा पुष्प कृषि उद्यान कृषि आधारित या कृषि आधारित ऐसे उद्योगों जो पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल से देशी माल से उत्पादों का उत्पादन करती हैं इस अंचल में अनुज्ञात किया जाएगा ;  
परंतु इनसे प्रदूषित बहिस्राव, उत्सर्जन या संघात नहीं होता हो।
- (iii) गैर नगर पालिका क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुज्ञात किया जाएगा :

(क) लारजर डेरी, पाल्ट्री, मसरूम-रियरिंग और समवर्गी कृषि क्रियाकलापों की प्रकृति के अन्य यूनियो और उससे संबद्ध सन्निर्माणों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जा सकेगा जो अधिकतम 1/8 निर्मित क्षेत्र के अधीन होगा जिसे मानीटरिंग समिति द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

(ख) लघु कृषि आधारित उद्योगों से सम्बद्ध संरचनाओं, स्थानीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और स्थानीय कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण या भंडारण की आवश्यकता से संबंधित

क्रियाकलापों को भी अनुज्ञात किया जा सकेगा जो सामान्यतया “ कृषि नहीं है” अनुज्ञा अपेक्षाओं और 1/8 में अधिकतम निर्मित क्षेत्र के अधधीन होगा ।

**(ग) खदान क्रिया और खनन :-** खदान क्रिया और खनन क्रियाकलाप इस क्षेत्र में प्रतिबंधित होंगे । पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में कोई नया खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा । तथापि मानिटरी समिति केवल स्थानीय निवासीय गृह निर्माण के संनिर्माण और परम्परागत सड़क अनुरक्षण संकर्म के लिए अपेक्षित सामग्रियों की सीमित खदान क्रिया के लिए विशेष अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकारी होगी :

परंतु ऐसी खदान क्रिया वन भूमि पर नहीं की जाती हो ।

**(घ) वृक्ष :-** पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के भीतर की भूमि चाहे वन, सरकारी राजस्व या निजी भूमि हो वन भूमि की दशा में राज्य सरकार और सरकारी राजस्व और निजी भूमि की दशा में संबंधित जिला कलेक्टर की बिना पूर्व अनुज्ञा के जो उस प्रक्रिया के अनुसार होगी जो राज्य सरकार द्वारा प्तिहित की जाएगी कोई वृक्ष नहीं गिराया जाएगा, परन्तु यह कि जिला कलेक्टर इस शक्ति को उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा ।

**(उ) पर्यटन :-** पर्यटन क्रियाकलाप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होंगे । पर्यटन मास्टर प्लान आंचलिक मास्टर प्लान का एक घटक रूप भी होगी ।

पर्यटन मास्टर प्लान पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के चलाये जाने की क्षमता के विस्तृत अध्ययन पर आधारित होगी जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी । सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटन के लिए विकास या पर्यटन क्रियाकलाप जो विद्यमान है, के विस्तार की अनुज्ञा केवल इस पर्यटन प्लान या चलाए जाने की क्षमता के अध्ययन की परिसीमाओं के भीतर ही दी जाएगी । अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाने तक नए पर्यटन क्रियाकलाप और पर्यटन के लिए विकास या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिकथित मार्गदर्शनों के अधधीन मानिटरींग समिति द्वारा विस्तृत विश्लेषण किए जाने और अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही अनुज्ञापित किया जाएगा ।

**(च) प्राकृतिक विरासत :-** अंचल में भूतयान प्राकृतिक विरासत के स्थलों की पहचान विशिष्ट रूप से, चट्टान निर्माणों, जल प्रपातों, फूलों, तंगघाटियों, उपवनों, गुफाओं, रथलो, सैरों, सवारियों इत्यादि के रूप में की जाएगी और प्लानों को उनके प्राकृतिक स्थापन में उनके संरक्षण को आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लानों में सम्मिलित किया जाएगा । इन स्थलों पर या उनके निकट संनिर्माण क्रियाकलापों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शन तय किए जाएंगे जिसके अंतर्गत पर्यटक को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी है । अंचल में सभी जीन पूल आरक्षित क्षेत्रों को परिरक्षित किया जाएगा । राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके संरक्षण या परिरक्षण के लिए उचित प्लान तैयार करेगी । ये प्लान आंचलिक मास्टर प्लान और उप-आंचलिक मास्टर प्लानों के भाग रूप होंगे ।

**(छ) मानव निर्मित विरासत :-** ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, आर्टीफेक्टों, क्षेत्रों और प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण, विशेषकर उनके बाहरी स्वरूप (और जहां उचित समझा जाए, वहां अंदरूनी स्वरूप) के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी और उसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर आंचलिक मास्टर प्लान और उप आंचलिक मास्टर प्लानों में सम्मिलित किया जाएगा । राज्य सरकार, अंचल में, विशेष रूप से महाबलेश्वर और पंचगणी म्युनिसिपल सीमाओं के भीतर तथा क्षेत्र महाबलेश्वर में भवन और अन्य क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बना सकेगी, जिससे कि शहरों का और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल का विशेष स्वरूप और सुभिन्न परिवेश बनाए रखा जा सके ।

**(ज) विरासत स्थलो (प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों) पर या उनके आसपास विकास और संनिर्माण क्रियाकलापों का विनियमन, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1995 में बनाए गए, समय-समय पर यथा संशोधित और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थलों के लिए प्रारूप भाडल, विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।**

(झ) भूगर्भ जल :- भूगर्भ जल के निष्कर्षण की अनुज्ञा केवल प्लाट के स्वामी के सदभावी कृषि और घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी। प्राइवेट औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवासीय संपदा/कम्प्लेक्सों के लिए भूगर्भ जल के निष्कर्षण के लिए राज्य भूगर्भ जल बोर्ड की अनुज्ञा अपेक्षित होगी। भूगर्भ जल के विक्रय की मानीटरिंग समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ञ) प्लास्टिक का उपयोग :- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल में प्लास्टिक का उपयोग निगरानी समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ट) बहिस्त्रावों का निस्सारण :- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल में किसी अनुपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण प्रतिषिद्ध है। किसी बहिस्त्राव का चाहे वह उपचारित हो अथवा अनुपचारित अंचल के भीतर, किसी जलाशय/जलाशयों और जल स्रोत/स्रोतों में निस्सारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट :- स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय घटकों में पृथक् करने की योजना बनाएंगे। जैव निम्नीकरणीय सामग्री अधिमानतः कम्पोस्टिंग या कृमि पालन द्वारा पुनः चक्रित की जा सकेगी, अकार्वनिक सामग्री पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य अवस्थानों पर व्यवस्थित की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ठोस अपशिष्ट पद में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और उद्यान संबंधी अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं।

3. (क) भारत सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति गठित करेगी। अधिसूचना के उपरोक्त उपबंधों के अलावा, मानीटरिंग समिति को पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के भीतर शोर प्रदूषण को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियां होंगी। मानीटरिंग समिति को यातायात विशेषकर पारिस्थितिकी संवेदनशील अंचल के अंदर यातायात को विनियमित करने की भी शक्तियां होंगी। जब मास्टर प्लान को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तब ऐसा विनियमन मास्टर प्लान के उपबंधों के अनुरूप होगा। मानीटरिंग समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, के प्रतिनिधि और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के (विरासत संरक्षण सहित) कम से कम दो प्रतिनिधि (जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित होंगे। समिति की सदस्य संख्या, अध्यक्ष सहित, दस से अधिक नहीं होगी।

(ख) निगरानी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध उसके ध्यान में आते हैं तो वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन उनकी शिकायतें फाइल करे।

(ग) निगरानी समिति द्वारा प्राधिकृत कोई समिति या कोई अधिकारी या कोई सदस्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत होगा।

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग और उच्च स्तरीय निगरानी समिति को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप से प्रगणित कृत्य और उससे आनुषंगिक सभी बातें (समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाग प्रभाग निर्वाण अधिसूचना, तारीख 27 जनवरी, 1994 के उपबंधों के अधीन ऐसे कृत्यों को छोड़कर जिनका पालन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाना यथा अपेक्षित है) करने के लिए सशक्त करता है।

5. परंतु यह कि इस अधिसूचना के अधीन प्रत्यायोजित कृत्यों की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील पर्यावरण और वन मंत्रालय को की जाएगी।

[फा. सं. जे-20011/7/98/आई.ए-III]

डा. पी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

अधिसूचना  
शहरी विकास विभाग  
मंत्रालय, बंबई-400032  
तारीख, 29 अप्रैल, 1983

महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966

सं. टी पी एस 1982/4507(क)-यू डी 7 : महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, 1966 (महाराष्ट्र का 1966 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए “महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश” नामक एक प्रदेश का गठन करती है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की महाबलेश्वर तहसील की सीमाओं के भीतर का संपूर्ण क्षेत्र और सतारा जिले की जाओली तहसील के निम्नलिखित गांव होंगे -

- (1) बोंदारवाडी
- (2) भूटेगढ़
- (3) दानवाली
- (4) तालोशी
- (5) उम्बरी

उपर्युक्त अनुसार सम्मिलित क्षेत्र को दिखाने वाले महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश की सीमाओं को उपदर्शित करने वाले रेखांक की प्रति निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, अर्थात् :-

- (1) नगर योजना निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ।
  - (2) सतारा का कलक्टर
  - (3) महाबलेश्वर और जाओली के तहसीलदार
  - (4) महाबलेश्वर म्युनिसिपल परिषद्
  - (5) पंचगनी म्युनिसिपल परिषद्
  - (6) नगर योजना सहायक निदेशक, सतारा
- महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम से ।

हस्ताक्षरित

(आर.बी. डोनाल्ड)  
उप सचिव सरकार

**महाबलेश्वर पंचगनी**  
**पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंचल**  
**महाबलेश्वर पंचगनी**

क. महाबलेश्वर पंचगनी प्रदेश का क्षेत्र = 237.28 वर्ग कि.मी.

ख. उपर्युक्त में

- (1) महाबलेश्वर म्युनिसिपल क्षेत्र = 19.55 वर्ग कि.मी.
- (2) पंचगनी म्युनिसिपल क्षेत्र = 6.16 वर्ग कि.मी.
- (3) म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर गाओथोस = 0.95 वर्ग कि.मी.

ग. म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर विकास जोन = 1.66 वर्ग कि.मी.

घ. वन अंचल = 123.96 वर्ग कि.मी.

ङ. हरित अंचल = 83.72 वर्ग कि.मी.

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2001

**S.O. 52(E).**— Whereas a notification under sub section (1) and clause (v) of sub section (2) of Section 3 of the Environment Protection Act, 1986, inviting objection or suggestion against the notification notifying the Mahableshwar Panchgani as an Eco sensitive region and imposing restriction on industries, operations, processes and other developmental activities in the region which have detrimental effect on the environment was published in S.O. No. 693(E) dated the 25<sup>th</sup> July, 2000;

And whereas all objections or/and suggestions received have been duly considered by the Central Government

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and all other powers vesting in its behalf, the Central Government hereby notify the Mahableshwar Panchgani Region (as defined in the Government of Maharashtra notification of 29<sup>th</sup> April, 1983 as an Eco Sensitive Zone. (Copy attached as Annexure). The Region shall include the entire area within the boundaries of the Mahableshwar Tehsil and the villages of Bondarwadi, Bhuteghar, Danwali, Taloshi and Umbri of Jaoli Tehsil of the Satara District in the Maharashtra state.

1. All activities in the forests (both within and outside municipal areas) shall be governed by the provisions of the Indian Forests Act, 1927 (16 of 1927) and Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980). All activities in the sanctuaries and national parks shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).
2. The following activities are proposed to be regulated in the Eco-Sensitive Zone.

**(a) Zonal Master Plan: -**

- (i) A Master plan for the entire Zone shall be prepared by the State Government and approved by the Ministry of Environment and Forests in the Government of India within a period of two years from the date of publication of this notification. The Master Plan shall be published by following a procedure similar to that prescribed under the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966. The Master Plan shall clearly indicate those limited areas where industries may be permitted.

(ii) The said Master Plan shall clearly demarcate all the existing forests, green areas, horticultural areas such as strawberry farms, raspberry farms, orchards, tribal areas, and other environmentally sensitive areas. No change of land use from green uses such as horticultural areas, agriculture, parks and other like places to non-green uses shall be permitted in the Master Plan. The Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulating traffic, especially through traffic in the Eco sensitive zone.

(iii) The areas within and outside Mahableshwar and Panchgani municipal areas shall have Sub-Zonal Master Plans which may be prepared by the State Government as a component of the Zonal Master Plan and concurrence of the Ministry of Environment and Forests shall be obtained on this.

This Sub-Zonal Master Plan shall include building regulations for the gaathan areas.

(iv) Pending the preparation of and approval by the Ministry of Environment and Forests to the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans referred to above, there shall be no increase in the existing parameters of permissible Floor Area Ratio, permissible height, permissible maximum number of storeys and permissible ground coverage; and there shall also be no reduction in the Forest Zone Green Zone Agricultural Zone. Absolute height of buildings shall not exceed 9 metres and number of storeys shall not exceed ground plus one.

**(b) Industrial Units: -**

(i) Location of industries shall be only in the designated industrial areas or estates and has to be as per guidelines drawn up by the Government of Maharashtra as well as the guidelines issued from time to time by the Ministry of Environment and Forests. However this would not apply to all those units which have obtained Consent to establish and all other statutory permissions and have commenced construction at site on or before the date of issue of this notification.

(ii) In future only non polluting non hazardous service industries, units making footwear from processed and ready made leather, floriculture, horticulture based or agro based industries producing products from indigenous goods from the Eco Sensitive Zone shall be permitted in this zone:

Provided that these do not result in polluting effluent, emission or impacts.

- (iii) In the non municipal areas, the following shall also be permitted:
- (a) Larger dairy, poultry, mushroom-rearing and other units in the nature of allied agricultural activities and structures connected therewith may be allowed with the prior permission of the competent authority subject to a maximum of 1/8<sup>th</sup> built up area, relaxable by the Monitoring Committee.
  - (b) Structures connected with small agro-based industries, activities related to the needs of the local village economy, and processing or storage of local agro-based products may be allowed subject to the usual “not agriculture” permission requirements and a maximum built up area of 1/8<sup>th</sup>.
- (c) **Quarrying and Mining:** - Quarrying and Mining activities shall be banned in this area. No fresh mining lease shall be granted in the Eco Sensitive Zone. However, the Monitoring Committee shall be the authority to give special permission for limited quarrying of materials required for the construction of local residential housing and traditional road maintenance work only; provided that such quarrying is not done on forestlands.
- (d) **Trees:** - There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or private lands within the Eco-Sensitive Zone, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per procedure which shall be prescribed by the State Government, provided that the District Collector shall not delegate this power to any subordinate officer below the rank of Sub-Divisional Officer.
- (e) **Tourism :-** Tourism activities shall be as per a Tourism Master Plan to be prepared by the Department of Tourism of the State Government in consultation with the Ministry of Tourism of Government of India and approved by the Ministry of Environment and Forests. The Tourism Master Plan shall also form a component of the Zonal Master Plan.
- The Tourism Master Plan shall be based on a detailed Carrying Capacity Study of the Eco-Sensitive Zone, which may be carried out by the State Government and submitted to the Ministry of Environment and Forests for approval within two years of the date of this notification. All new tourism activities, developments for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only within the parameters of this tourism plan or carrying capacity study. Till the Tourism Master Plan is submitted to Ministry of Environment and Forests for approval, new tourism activities and developments for tourism or expansion of existing tourism activities shall be permitted only after a detailed analysis is carried out and approved by the Monitoring Committee subject to guidelines laid down by Ministry of Environment and Forests.



- (f) **Natural Heritage:** - The sites of valuable natural heritage in the zone shall be identified, particularly rock formations, waterfalls, pools, gorges, groves, caves, points, walks, rides etc. and plans for their conservation in their natural setting shall be incorporated in the Zonal Master Plan and Sub Zonal Master Plans. Strict guidelines shall be drawn up by the State Government to discourage construction activities at or near these sites including under the garb of providing tourist facilities. All the gene pool reserve areas in the zone shall be preserved. The State Government may draw up proper plans for their conservation or preservation within one year from the date of publication of this notification. These plans shall form a part of the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans.
- (g) **Man-made heritage:** - **Buildings,** structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetical, and cultural significance shall be identified and plans for their conservation, particularly their exteriors (and wherever deemed appropriate their interiors also) shall be prepared and incorporated in the Zonal Master Plan and Sub-Zonal Master Plans within one year from the date of publication of this notification. Guidelines may be drawn up by the State Government to regulate building and other activities in the Zone, particularly in Mahableshwar and Panchgani municipal limits and in Kshetre Mahableshwar, so that the special character and distinct ambience of the towns and the eco sensitive zone is maintained.
- (h) Development or construction activity at or around heritage sites (both natural and man-made) shall be regulated in accordance with the Draft Model Regulations for Conservation of Natural and Man-made Heritage formulated by the Ministry of Environment and Forests in 1995 as amended from time to time and circulated to all State Governments and Union territory Administrations).
- (i) **Ground Water:** - Extraction of ground water shall be permitted only for the bona fide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot. Extraction of ground water for private industrial/commercial/residential estates/complexes shall require prior permission from the State Ground Water Board. No sale of ground water shall be permitted except with prior approval of the Monitoring Committee.
- (j) **Use of plastics:** - The use of plastics within the Eco Sensitive Zone shall be regulated by the Monitoring Committee.

**(k) Protection of Hill Slopes:** - The Master Plan shall indicate areas on hill slopes where construction shall not be permitted.

**(l) Discharge of effluents:** - The discharge of any untreated effluent is prohibited within the Eco Sensitive Zone. No effluent, either treated or untreated, shall be permitted to be discharged into water body/s and water source/s within the zone.

**(m) Solid Wastes:** - The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components. The biodegradable material may be recycled preferably through composting or vermiculture; the inorganic material may be disposed of at environmentally acceptable locations. It is clarified that the term solid wastes include domestic, industrial, commercial and garden wastes.

3 (a) The Government of India shall constitute a High Level Monitoring Committee to ensure compliance with the provisions of this notification. Besides the above provisions of the notification, the monitoring committee shall have the powers to regulate and control noise pollution within the Eco sensitive zone. The monitoring committee shall also have powers to regulate traffic especially through traffic within the Eco sensitive zone; once the Master Plan is approved by the Ministry of Environment and Forests in Government of India such regulation shall be in conformity with the provisions of the Master Plan. The monitoring committee shall include representative(s) of the Ministry of Environment and Forests, Central pollution Control Board and at least two representatives of non-government organisations working in the field of environment (including heritage conservation) (to be nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India). The membership of the committee including Chairman shall not exceed ten.

(b) It shall be the duty of the Monitoring Committee to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 if offences under the said Act come to its notice.

(c) The Committee or any officer or member of the Monitoring Committee authorised by the Committee shall be authorised to file complaints under the Environment (Protection) Act, 1986.

4. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with section 23 of the said Act, the Ministry of Environment and Forests, Government of India empowers the Urban Development Department, Government of Maharashtra and the High Level Monitoring Committee to discharge the functions specifically enumerated in this notification and to do all things incidental thereto, (except the functions as are

required to be performed by the Central Government under the provisions of the Environment Impact Assessment notification of 27th January, 1994 as amended from time to time).

5. Provided that in respect of functions delegated under this notification, an appeal from any order shall lie to the Ministry of Environment and Forests.

[F. No. J-20011/7/98/IA-II]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy

## ANNEXURE

### Urban Development Department

#### NOTIFICATION

Bombay the 29th April, 1983

**Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.**—No TPS. 1982/4507 (a)-UD 7 : In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section (3) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as "the said act"), to Government of Maharashtra, hereby establishes a region for the purpose of the said Act to be named as the "Mahableshwar Panchgani Region" which shall include the entire area within the boundaries of Mahableshwar Tehsil and the villages of—

- (1) Bondarwadi
- (2) Bhuteghar
- (3) Danwali
- (4) Taloshi
- (5) Umbri

Of Jaoli Tehsil of the Satara District in the Maharashtra State. A copy of the plan showing boundaries of Mahableshwar Panchgani Region showing the area included as aforesaid is available for inspection at offices of the following officers namely :

- (1) The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune
- (2) The Collector of Satara
- (3) The Tahasildars of Mahableshwar and Jhaoli
- (4) The Municipal Council, Mahableshwar
- (5) The Municipal Council, Panchgani
- (6) The Assistant Director of Town Planning, Satara.

By Order and in the Name of the Governor of Maharashtra.

Sd/-

R. B. DONALD, Dy. Secy.

A. Area of Mahableshwar Panchgani Region	=	237.28 sq. kms.
B. <u>Of the above</u>		
(1) Mahableshwar Municipal Area	=	19.55 sq. kms.
(2) Panchgani Municipal Area	=	6.16 sq. kms.
(3) Goatherds outside Municipal limits	=	0.95 sq. kms.
C. Residential Zone outside Municipal limits	=	1.66 sq. kms.
D. Forest Zone	=	123.96 sq. kms.
E. Green Zone	=	83.72 sq. kms.

